

ग्रामीण विकास में सरकारी बैंको की भूमिका

¹शिव कुमार कंवर, ²डॉ.ए.राजशेखर

¹शोध छात्र, ²प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष

^{1,2}भूगोल विभाग, कलिंगा विश्वविद्यालय, नवा रायपूर, छत्तीसगढ़ – 492101

बैंक पर विश्वास कम होने से वित्तीय समावेशन धीमा पड़ता है। ग्रामीण विकास तभी संभव है जब बैंक आवश्यकता के समय प्राथमिकता के आधार पर सहयोग करे। सारणी से स्पष्ट है कि अधिकांश ग्रामीण लोग बैंक को आपात स्थितियों में सहयोग न करने वाला मानते हैं। केवल लगभग 20% ही सकारात्मक अनुभव रखते हैं। यह दर्शाता है कि बैंकिंग प्रणाली को ग्रामीण वास्तविकताओं के अनुरूप अधिक संवेदनशील, त्वरित और सुलभ बनाना आवश्यक है। यदि बैंक:

- त्वरित ऋण योजना,
- 24x7 डिजिटल सेवाएँ,
- ग्रामीण ATM उपलब्धता,
- ग्राहक सहायता डेस्क,
- सरल दस्तावेजीकरण

जैसी सुविधाएँ बढ़ाए तो ग्रामीण विकास में उसका योगदान और अधिक प्रभावी हो सकता है।

अतः सारणी से स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास को गति देने के लिए बैंक को सूचना प्रसार, वित्तीय साक्षरता शिविर, ग्राम सभाओं में जागरूकता अभियान, तथा सरल भाषा में योजना मार्गदर्शन बढ़ाना होगा, जिससे लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुँच सके।

सारणी क्रमांक 1.1

बैंक को ग्रामीण विकास में संस्थागत सहयोग किस रूप में करना चाहिए है ?

गरीब किसानों की मदद कर	301	60.2
ग्रामीण संरचना के विकास में मदद कर	156	31.2
किसी भी क्षेत्र में कर सकते	43	8.6

स्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण से प्राप्त

इस सारणी में ग्रामीण उत्तरदाताओं से यह जाना गया कि बैंक, विशेषकर एसबीआई को ग्रामीण विकास में किस प्रकार संस्थागत सहयोग प्रदान करना चाहिए। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 301 उत्तरदाताओं (60.2%) ने गरीब किसानों की मदद को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, 156 उत्तरदाताओं (31.2%) ने ग्रामीण संरचना के विकास को बैंक का संभावित सहयोग माना, जबकि 43 उत्तरदाताओं (8.6%) ने कहा कि बैंक किसी भी क्षेत्र में योगदान कर सकता है। ये आंकड़े ग्रामीण जनता की वास्तविक आवश्यकताओं, सामाजिक मांगों और बैंक से अपेक्षित भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करते हैं। 301 उत्तरदाताओं का यह मानना कि बैंक को गरीब किसानों की सहायता करनी चाहिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव को दर्शाता है। ग्रामीण भारत में अधिकांश परिवार खेती पर निर्भर हैं और किसान, विशेषकर छोटे और सीमांत किसान, वित्तीय संकट, बाजार जोखिम, प्राकृतिक आपदाओं और कर्ज चक्र में फँसने जैसी समस्याओं से जूझते हैं। कृषि प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और आधुनिक खेती के उपकरण खरीदने हेतु वित्तीय

सहायता यह प्राथमिकता दिखाती है कि ग्रामीण जनता बैंक को केवल वित्तीय संस्था नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा और कृषि स्थिरता की रीढ़ मानती है।

इस श्रेणी का उच्च प्रतिशत बताता है कि ग्रामीण विकास का मूल आधार कृषि है, और बैंक की नीतियाँ तभी प्रभावी होंगी जब वे सीधे किसान हित से जुड़ी होंगी। 31.2 % उत्तरदाताओं की राय 156 उत्तरदाता चाहते हैं कि बैंक ग्रामीण संरचना के विकास में भी भूमिका निभाए। ग्रामीण संरचना में सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पेयजल, मंडी, गोदाम, डिजिटल सेवाएँ, और सार्वजनिक सुविधाएँ शामिल हैं। यह समूह इस बात को दर्शाता है कि ग्रामीण जनता केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक एवं बुनियादी ढाँचे के विकास में भी बैंक की भूमिका देखना चाहती है। ग्रामीण विकास में संरचना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर आर्थिक प्रगति को धीमा कर देता है। 8.6 % उत्तरदाताओं की तटस्थ राय 43 उत्तरदाताओं ने कहा कि बैंक ग्रामीण विकास के किसी भी क्षेत्र में सहायता कर सकता है। यह समूह खुली सोच रखता है और बैंक की भूमिका को सीमित नहीं करता। ये उत्तरदाता मानते हैं कि जहाँ आवश्यकता हो वहाँ बैंक योगदान दे सकता है शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल सेवाएँ, SHG हर क्षेत्र में सहयोग प्रभावी हो सकता है। बैंक को परिस्थिति और स्थानीय मांग के अनुसार विकासात्मक कार्य करने चाहिए। यह श्रेणी बताती है कि ग्रामीण लोग बैंक को सामाजिक परिवर्तन में भागीदार के रूप में देखना चाहते हैं। सारणी के परिणाम यह स्पष्ट करते हैं कि ग्रामीण जनता बैंक की भूमिका से केवल लेन-देन नहीं बल्कि सामाजिक-आर्थिक विकास की भी अपेक्षा रखती है।

ग्रामीण विकास पर संभावित प्रभाव:

- गरीब किसानों को सहयोग मिलने से कृषि उत्पादन में वृद्धि
- किसानों की आर्थिक स्थिरता से पूरे ग्रामीण बाजार की गतिविधि बढ़ेगी
- संरचनात्मक विकास से शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और व्यापार में सुधार
- बैंक की बढ़ी हुई भागीदारी से वित्तीय समावेशन मजबूत होगा
- SHG एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा

बैंक यदि इन क्षेत्रों में सहयोग करता है तो ग्रामीण विकास की गति और अधिक तीव्र हो सकती है। सारणी क्रमांक 4.18 स्पष्ट रूप से दिखाती है कि ग्रामीण जनता की प्राथमिकता किसानों की आर्थिक सहायता है, जिसे वे ग्रामीण विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। इसके बाद ग्रामीण संरचना के विकास को महत्व दिया गया है, जो कि दीर्घकालीन विकास के लिए आवश्यक है। सबसे छोटी श्रेणी उन उत्तरदाताओं की है। जो बैंक की भूमिका को व्यापक और किसी भी क्षेत्र में संभावित मानते हैं। समग्र रूप से यह सारणी दर्शाती है कि ग्रामीण विकास के लिए बैंक को दोनों स्तरों आर्थिक (किसान सहायता) और सामाजिक (बुनियादी संरचना) पर सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

सारणी क्रमांक 1.2

क्या बैंक आपात स्थिति में सुविधाएं प्रदान करता है?

हमेशा	96	19.2
कभी-कभी	48	9.6
नहीं	356	71.2

स्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण से प्राप्त

यह सारणी ग्रामीण क्षेत्र के उत्तरदाताओं की उस धारणा को दर्शाती है, जिसमें यह आकलन किया गया कि क्या बैंक विशेषकर एसबीआई आपात स्थिति में त्वरित और आवश्यक बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने में सक्षम है। प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 19.2% उत्तरदाताओं ने कहा कि बैंक हमेशा आपात स्थिति में सहायता करता है, 9.6% ने कभी-कभी कहा और 71.2% उत्तरदाताओं ने माना कि बैंक आपात स्थितियों में आवश्यक सुविधाएँ प्रदान नहीं करता।

ये आंकड़े ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली की चुनौतियों, सेवाओं की सीमाओं और ग्रामीण विकास पर इसके प्रभावों को स्पष्ट रूप से सामने रखते हैं। क्योंकि ग्रामीण संदर्भ में आपातकालीन वित्तीय सहायता का महत्व कई प्रकार की हो सकती है जैसे

- अचानक स्वास्थ्य समस्या
- फसल नष्ट होना
- प्राकृतिक आपदा (सूखा, ओलावृष्टि, बाढ़)
- परिवार में आकस्मिक खर्च
- फसल खरीद या पशुपालन के लिए त्वरित पूंजी

ऐसे समय में यदि बैंक सहायता या त्वरित लेन-देन सुविधाएँ उपलब्ध कराता है, तो ग्रामीण परिवार आर्थिक संकट से बच सकते हैं। इसलिए यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि बैंक आपातकाल में त्वरित भुगतान, तत्काल ऋण, नकदी उपलब्धता और सहानुभूतिपूर्ण सेवा दें। 96 (19.2%) उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि बैंक उन्हें आपात स्थिति में सहायता करता है। यह छोटे प्रतिशत का समूह बताता है कि बैंक में कुछ सीमा तक उत्तरदायित्व और तत्परता मौजूद है, परंतु यह अनुभव सभी के लिए समान नहीं है। 48 उत्तरदाताओं ने बताया कि बैंक

आपातकालीन स्थितियों में कभी-कभी सहयोग करता है। इसका अर्थ है कि सेवाएँ नियमित, स्थायी या भरोसेमंद नहीं हैं। कभी कर्मचारी सहयोग करते हैं, कभी नहीं। कभी नेटवर्क या तकनीकी समस्या आ जाती है। कभी शाखा खुली हो तो सहायता मिल जाती है।

यह समूह दिखाता है कि बैंक की आपातकालीन सहायता योजना में निरंतरता की कमी है। 356 (71.2%) उत्तरदाताओं ने माना कि बैंक आपातकाल में सेवाएँ प्रदान नहीं करता। यह अत्यधिक उच्च प्रतिशत है और बैंकिंग तंत्र की कमज़ोरियों को उजागर करता है। आपात मामलों में तुरंत आर्थिक सहायता न मिलना ग्रामीण परिवारों को महाजन/साहूकार के पास जाने के लिए मजबूर करता है, जिससे कर्ज के जाल में फँसने की संभावना बढ़ जाती है। यह ग्रामीण विकास के लिए गंभीर बाधा है। बैंक की आपातकालीन सेवाओं का अभाव सीधे ग्रामीण विकास को प्रभावित करता है।

- किसान संकट के समय वित्तीय सुरक्षा से वंचित रह जाते हैं
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रभाव कम हो जाता है
- SHG गतिविधियों में बाधाएँ आती हैं
- अचानक खर्च होने पर ग्रामीण जनता उधार पर निर्भर होती है
- आर्थिक अस्थिरता ग्रामीण गरीबी को बढ़ाती है

संदर्भ ग्रंथ

1. अर्जुन कुमार मौर्य, जय शंकर शुक्ल. ग्रामीण विकास में कौशल विकास की भूमिका एवं अपेक्षाओं का अवलोकनार्थ अध्ययन (फैजाबाद (अयोध्या) जिला के विशेष संदर्भ में). *International Journal of Reviews and Research in Social Sciences*- 2022 (2022; 10(4):145-2.
2. रवि प्रकाश पाण्डेय, रामजी बंशकार. भारतीय ग्रामीण विकास में स्व-सहायता समूह का योगदान-एक आर्थिक अध्ययन (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में). *International Journal of Reviews and Research in Social Sciences*. 2024; 12(1):57-6. doi: 10.52711/2454-2687.2024.00011 <https://ijrrsonline.in/AbstractView.aspx?PID=2024-12-1-11>
3. Gautam, Rahul & Kanoujiya, Jagjeevan. (2022). Role of Regional Rural Banks in Rural Development and Its Influences on Digital Literacy in India. 5. 92-101.
4. Mr. Srinivasa.K.1.,& Challakumar J.A. Arul (2022) Regional Rural Banks and Rural Economic Development August 2022, *IJIRT* ,Volume 9 Issue 3 | ISSN: 2349-6002
5. Dhanda, Rakshanda. (2020). A Study on Role of STATE BANK OF INDIA in Financial Inclusion.
6. <https://www.researchexperts.in/role-of-the-literature-review-in-research/>
7. Purohit, Harsh & Bindra, Pawandeep Kaur in (2017), ROLE OF STATE BANK OF INDIA IN PROMOTING FINANCIAL INCLUSION IN INDIA., *IMPETUS – XAVIER'S INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, Volume VI , August 2017 .
8. Das, Dilip Ch. (201A Study on Microfinance and Rural Development with the initiative of nationalized Bank specially SBI in Assam, *International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)* ,A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal

ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print) ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print) Volume-IV, Issue-IV, January 2018, Page No. 46-52 Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711 Website: <http://www.ijhsss.com>

9. Bhople, Mangesh & Deshpande, Reetuja. (2023). EXPLORING THE ROLE OF STATE BANK OF INDIA IN PROMOTING SUSTAINABLE SHARED VALUE CREATION IN THE BANKING SECTOR. Shodha Prabha, Vol. 48, Issue 01, No. 7 : 2023
10. Patel L. & Shah Nimish (2014), "India's Skills Challenge: Reforming Vocational Education and Training to Harness the Demographic Dividend". ISBN-10: 0199452776, ISBN-13: 978-0199452774.
11. Shrivastava P., Techno-Vocational Skills Acquisition and Poverty Reduction Strategies, ISBN13: 9783659363672 ISBN10: 3659363677, Publisher: LAP